



लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए  
प्रधानमंत्री पुरस्कार

Prime Minister's Awards for Excellence  
in Public Administration

2011-2012

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
भारत सरकार

Department of Administrative Reforms and Public Grievances  
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions  
Government of India





लोक प्रशासन में  
उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार  
**Prime Minister's Awards for  
Excellence in Public Administration  
2011 - 2012**

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
भारत सरकार

Department of Administrative Reforms and Public Grievances  
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions  
Government of India

---

---

## विषय-सूची

1. वर्ष 2011-2012 के लिए पुरस्कार विजेता	
(i) दंतेवाड़ा में शैक्षणिक पहल	1-2
(ii) डलिया जलाओ: मैला ढोने से आजादी और पूर्ण स्वच्छता की ओर बढ़ना	3-4
(iii) हुबली-धारवाड़ नगर के जलाशयों एवं उद्यानवनों का संरक्षण और नगर में सांस्कृतिक अभिवृद्धि	5-6
(iv) गन्ना सूचना प्रणाली	7-8
(v) कर्नाटक में वाणिज्य कर प्रणाली का संपूर्ण रूपांतरण	9-10
(vi) सिक्किम हिमालय की चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिवेश में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्कृष्टता	11-12
(vii) कौशल्य वर्धन केंद्र	13-14
2. वर्ष 2010-11 के लिए पुरस्कार विजेता	15-16
3. वर्ष 2009-10 के लिए पुरस्कार विजेता	17-18
4. वर्ष 2008-09 के लिए पुरस्कार विजेता	19-21
5. वर्ष 2007-08 के लिए पुरस्कार विजेता	22-24
6. वर्ष 2006-07 के लिए पुरस्कार विजेता	25-29
7. वर्ष 2005-06 के लिए पुरस्कार विजेता	30

---

---

---

---

## CONTENTS

1. Awardees for the Year 2011-12	
(i) Educational Initiatives in Dantewada	1-2
(ii) Daliya Jalao: Liberating Manual Scavengers and Moving Towards Total Sanitation	3-4
(iii) Saving Open Spaces and Urban Lakes (SOUL) and Cultural Rejuvenation of the Twin City of Hubli - Dharwad	5-6
(iv) Sugarcane Information System, Uttar Pradesh	7-8
(v) Transformation of Commercial Tax Regime in Karnataka	9-10
(vi) Excellence in Rural Management and Development in the Challenging Physical Environment of the Sikkim Himalaya	11-12
(vii) Kaushalya Vardhan Kendra	13-14
2. Awardees for the Year 2010-11	15-16
3. Awardees for the Year 2009-10	17-18
4. Awardees for the Year 2008-09	19-21
5. Awardees for the Year 2007-08	22-24
6. Awardees for the Year 2006-07	25-29
7. Awardees for the Year 2005-06	30

---

---

**पहल - दंतेवाड़ा में शैक्षणिक पहल**

पुरस्कार विजेता का नाम - श्री ओमप्रकाश चौधरी  
जिलाधिकारी, दंतेवाड़ा

**परियोजना संक्षेप में**

दक्षिण बस्तर और दंतेवाड़ा को नक्सलवाद की घटनाओं और हिंसा के लिए जाना जाता है। इसके फलस्वरूप बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं और वर्तमान साक्षरता दर 33 प्रतिशत के निम्न स्तर पर है। चरमपंथियों को रोकने का एकमात्र रास्ता यह है कि भावी पीढ़ी को हत्या आधारित इस विचारधारा को अपनाने से रोका जाए। इसको ध्यान में रखते हुए श्री ओमप्रकाश चौधरी, जिलाधिकारी ने मानसिक रूपांतरण के एक मिशन की शुरुआत की।

**कार्यान्वयन विशेषताएं**

- स्कूल छोड़ चुके सभी बच्चों के लिए आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था की गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए 500 सीटों वाले आवासीय परिसरों की मंजूरी दे दी है।
- किसी भी सामुदायिक स्कूल को बंद नहीं किया जाना चाहिए। जैसे ही स्थिति बेहतर होगी इन स्कूलों को अधिक महत्व दिया जा सकता है।
  - जिन स्थानों में संघर्ष के कारण स्कूल बंद अथवा चरमपंथियों द्वारा नष्ट कर दिए गए थे, वहां स्थानीय लोगों की सहायता से पंचायतों का आकलन किया गया।
  - स्कूल छोड़ चुके बच्चों का सर्वेक्षण कर उनका पूर्व निर्मित स्कूल भवनों में नामांकन कराने के लिए स्वयंसेवकों (अनुदेशक) के रूप में शिक्षित और बेरोजगार स्थानीय लड़कों और लड़कियों को नियोजित किया गया था। प्रत्येक नामांकन के लिए इन स्वयंसेवकों को प्रोत्साहन राशि दी गई।
  - जहां स्थायी स्कूल भवन संभव नहीं है वहां राष्ट्रीय बांस मिशन द्वारा प्रमाणित पूर्व निर्मित स्कूल भवनों को स्थापित किया गया है।
  - बच्चों और उनके अभिभावकों को आकर्षित करने के लिए शिक्षा को और रुचिकर बनाया गया ताकि वे दूर-दराज से भी अपने बच्चों को भेजें। बाल प्रतिभा उत्सव, ग्रीष्मकालीन कैंप आदि जैसे कार्यक्रमों में बच्चों को अपनी प्रतिभा को व्यक्त करने का मंच उपलब्ध कराया गया।
  - अवसंरचना रिकार्ड समय में तैयार की गई और वर्तमान में 21 पोटा केबिन/आवासीय स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा है।

**तमन्ना:** सभी स्तर के बच्चों के दृष्टिकोण को विस्तृत बनाने के लिए जिला मुख्यालय में एक विज्ञान संग्रहालय, एक जिला पुस्तकालय, एक दृश्य-श्रव्य रंगमंच का कार्य एक माह में पूरा किया गया।

**शिक्षा का अधिकार का अक्षरशः कार्यान्वयन:** शिक्षा का अधिकार में समाज के वंचित वर्ग के 25 प्रतिशत बच्चों के नामांकन की परिकल्पना की गई है। किंतु दंतेवाड़ा

## Category - Individual

---

### Initiative - Educational Initiatives in Dantewada

Name of the Awardee - Shri Omprakash Choudhary  
Collector, Dantewada

#### Project in Brief

South Bastar and Dantewada are known for incidences of naxalism and consequent violence. As a consequence, children drop out of school and the literacy rate is currently as low as 33 percent. The only way to contain extremism is to prevent future generations from following this ideology based on murders. With this in view, Shri Omprakash Choudhary, District Collector embarked on a mission of mental transformation.

#### Implementation Highlights

- Residential facilities are provided to all out-of-school children. Ministry of Human Resource Development (MoHRD) has sanctioned 500 seater residential campuses for the out-of-school children.
- No community school must be closed. As the situation gets better, these schools can be given more emphasis.

Assessment of panchayats was done with the help of the locals, in places which were shut down due to conflicts or destroyed by the extremists.

- Educated and unemployed local boys and girls were employed as volunteers (Anudeshaks) for the survey of drop out children and enrolling them in prefabricated structures. Incentives were given to these volunteers for every enrolment.
- In cases where permanent structures are not possible, the district administration has installed pre-fabricated structures certified by the National Bamboo Mission.
- Education was made interesting to attract children and their parents, so that they will send their children even from far off places. Activities like Children Talent Festival, summer camps etc. provided children with a platform to express their talent.
- The infrastructure was created in record time and 21 pota cabins/ residential schools are currently under construction.

**Tamanna:** With a view to broaden the horizons of all levels of children, a science museum, a district library and an audio visual theatre were completed in a month's time at the district headquarters.

**Implementation of the provisions of the Right to Education (RTE) in letter and spirit:** The RTE envisages enrolment of 25 percent of the

जैसे स्थानों में इनका लाभ नहीं मिल पाता है क्योंकि यहां आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। अतः सरकारी सहायता वाले स्कूल को आवासीय सहायता दी जाती है ताकि वंचित समुदायों के बच्चे भी स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सकें।

**उच्च विद्यालय शिक्षा:** दंतेवाड़ा में 38,000 विद्यार्थियों (1 से 8वीं कक्षा तक) में से 9वीं से 12वीं तक केवल 5,116 बच्चे ही पहुंच सके थे। इस समस्या का समाधान करने के लिए आवासीय सहायता प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण जंक्शनों से समूहों का चयन किया गया। अतः इससे नामांकनों की संख्या में वृद्धि हुई और शिक्षा की गुणवत्ता भी बेहतर हुई।

**छू लो आसमान:** यह कार्यक्रम 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की एक पहल है। थोड़े से बच्चों के लिए विज्ञान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की कठिनाइयों को महसूस करते हुए एक साझा केंद्रीकृत स्थल का चुनाव किया गया ताकि इस स्थान के सभी बच्चों को शिक्षा दी जा सके। इस पहल के लिए जिले से सभी योग्य और अनुभवी शिक्षकों का चयन किया गया था।

**शिक्षा शहर:** जिला प्रशासन ने आवासीय और क्लास रूम शैक्षिक सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रु० की लागत से 97 एकड़ में उपनगर बसाने की शुरुआत की है।

**कौशल शिक्षा:** जिन विद्यार्थियों को कोई बुनियादी साक्षरता नहीं है, उनके भविष्य को संवारने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर एक आजीविका महाविद्यालय की स्थापना की गई थी इसमें 10वीं और 12वीं पास बेरोजगार युवकों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। समन्वय और भागीदारी के जरिए इंडिकेंट, टूमरो फाउंडेशन, लार्सन एंड टूब्रो जैसे संगठन कौशल निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। प्रशिक्षित युवकों को उद्योगों से संपर्क कर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

### परिणाम

- इस पहल का मुख्य कार्य समाज के वंचितों के लिए शिक्षा और साक्षरता है। किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा और कौशल निर्माण उनके व्यक्तित्व का और विकास करेगा और इससे उन्हें अधिक रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- व्यवस्था के प्रति विश्वास में वृद्धि हुई है क्योंकि अब दूर-दराज के क्षेत्रों के गांवों से लोग अपने बच्चों को शिक्षित कराने के लिए आगे आए हैं तथा सरकार और लोगों के बीच अंतर कम हुआ है।
- नामांकन, उत्तीर्ण प्रतिशतता, युवाओं के रोजगार में काफी वृद्धि हुई है। 8वीं कक्षा से 98 प्रतिशत विद्यार्थी 9वीं कक्षा में आए हैं।
- लाभार्थी जिले में मौजूदा शिक्षा प्रणाली में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं।

## Category - Individual

---

---

children from the deprived society. But in places like Dantewada, these slots remain unutilised as there is no provision for residential facilities. Hence, the schools with government help are providing residential facilities so that students of marginalized communities may avail of school education.

**High School Education:** In Dantewada out of 38,000 students (from classes 1<sup>st</sup> to 8<sup>th</sup>), only 5,116 make it to the classes 9<sup>th</sup> to 12<sup>th</sup>. To address the problem, clusters from important junctions were chosen to provide residential support. It, thus, increased the enrolment numbers and also improved the quality of education.

**Chhoo Lo Asmaan:** The programme is an initiative for qualitative improvement in Science Education in 11<sup>th</sup> and 12<sup>th</sup> standard. Realizing the difficulty of bringing quality teaching in science for a handful of children, a common centralized residential location was chosen to bring in all the students to this location. All the qualified and experienced teachers from the district were selected for this initiative.

**Education City:** The district administration started establishing 97 acres of township at the cost of ` 100 crore dedicated exclusively for the residential and classroom educational facilities.

**Skill Education:** To add value to those students who have no basic literacy levels, a livelihood college was established on a public private partnership model. The main focus is on the 10<sup>th</sup> and 12<sup>th</sup> class pass unemployed youth. Through coordination and participation of organizations like Indicant, Tomorrow Foundation, Larsen & Toubro, skill building is imparted. The trained youth are then provided employment through, linkages to the industries.

### Outputs/Outcomes

- The key functions of the initiative are the education and literary programs to those who are disadvantaged in the society. No child is deprived of education and moreover skill building adds value to their personality and helps secure job.
- Increase in the faith in the system, as people from the interior villages now come forward to educate their children and thus the gap between government and the people has reduced.
- Enrolment, pass percentage, employment for the youth has improved at a high rate. 98 percent of the students from the 8<sup>th</sup> class have moved on to the 9<sup>th</sup> class.
- The beneficiaries are realizing the quantitative and qualitative change in the education system prevailing in the district.



**पहल - डलिया जलाओ: मैला ढोने से आजादी और पूर्ण स्वच्छता की ओर बढ़ना**

पुरस्कार विजेता का नाम - श्री अमित गुप्ता, भा.प्र.सेवा, तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं, उत्तर प्रदेश

**परियोजना संक्षेप में**

संसद के 'मैला ढोने वाले कर्मियों का नियोजन और शुष्क शौचालयों का निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993' और जनहित याचिका पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2003 के निर्णय में सिर पर मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया है। किंतु यह प्रथा अभी भी बदायूं जिले में जारी थी और यह पहल इस प्रथा का उन्मूलन करने के लिए की गई थी। यह निर्णय लिया गया कि गांवों में टोकरी और झाड़ू का संग्रह कर उसे सबके सामने जलाया जाए। सिर पर मैला ढोने वाले कर्मियों के लिए एक पुनर्वास पैकेज तैयार किया गया। उन्हें सरकार की विभिन्न ऋण स्कीमों, पेशन स्कीमों, बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति, ग्रामीण आवास योजना और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण का लाभ दिया गया। सिर पर मैला ढोने वाले समुदाय ने इस प्रथा का उन्मूलन करने के लिए स्वयं को संगठित किया। अतः उनका सामाजिक समावेश सुनिश्चित किया गया। ग्रामीण क्षेत्र के सभी शुष्क शौचालयों को जल-प्रवाह शौचालयों में परिवर्तित कर दिया गया।

**कार्यान्वयन विशेषताएं**

- यह कार्य जुलाई, 2010 में शुरू हुआ तथा जुलाई, 2011 तक सभी सफाई कर्मियों को मुक्त करा लिया गया और उनका पुनर्वास किया गया। शुष्क शौचालयों को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया।
- दैनिक रिपोर्टिंग, समीक्षा, खुली ग्रामीण बैठक और इसी बैठक में हकदारियों का वितरण, बाल्मीकि समुदाय की सहभागिता और उनके नेता की भागीदारी जैसे कार्यकलापों ने इस पहल में अभूतपूर्व पारदर्शिता सुनिश्चित की है।
- इस पहल के सबसे महत्वपूर्ण स्टेकधारक मैला ढोने में लगे लोग थे। गांव में मैला ढोने की अंत के प्रतीक के रूप में मैला ढोने की टोकरी को जलाने (डलिया जलाओ) की जिला प्रशासन की कार्यनीति इस अभियान की पहचान बन गई। इस समुदाय के लोगों की सेवाओं का उपयोग शौचालय के निर्माण में राजमिस्त्री के रूप में लेने की नीति ने उन्हें अपने परिवर्तन का एजेंट बना दिया। अतः इस भागीदारी पद्धति ने इस पहल को स्वयं को मजबूत करने का जरिया बना दिया।
- जिले का बाल्मीकि संगठन अर्थात् राष्ट्रीय बाल्मीकि जन विकास मंच जो बाल्मीकि सेना के नाम से लोकप्रिय है, आरंभ से ही इस अभियान में शामिल था। जिला प्रशासन के दृष्टिकोण और सरोकार के परिणामस्वरूप बाल्मीकि सेना ने मैला ढोने वाले कर्मियों को मुक्त करने के लिए जोरदार प्रयास किए। इससे उनके समुदाय के साथी सदस्य, जो मैला ढोने की प्रथा में लगे थे, उन पर सामाजिक दबाव पड़ा।

### **Initiative - Daliya Jalao: Liberating Manual Scavengers and Moving Towards Total Sanitation**

Name of the Awardee - Shri Amit Gupta, IAS, then District Magistrate, Budaun, Uttar Pradesh

#### **Project in Brief**

The Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 of Parliament and Hon'ble Supreme Court ruling in PIL, 2003 have banned the practice of manual scavenging. But the practice was still continuing in Budaun district and an initiative was taken to eliminate it. It was decided to collect baskets and brooms in the village and burn them in the presence of everyone. A rehabilitation package for those involved in manual scavenging was developed. They were given the benefit of various loan schemes of the government, pension schemes, special scholarships for children, rural housing schemes and skill up-gradation training. The community of manual scavengers was involved and they organized themselves to eliminate manual scavenging. Their social inclusion was thus ensured. All dry toilets in rural areas were converted to flush latrines.

#### **Implementation Highlights**

- The work started in July 2010 and by July 2011, all the scavengers had been rescued and rehabilitated. Dry latrines were also phased out fully.
- Activities like daily reporting, reviews, open village meetings and distribution of entitlements in the meetings itself, involvement of Balmiki community and participation of its leaders have ensured unprecedented transparency in the initiative.
- The most important stakeholders of this initiative were the people engaged in the work of manual scavenging. The strategy of the district administration to mark the ending of manual scavenging in villages with the burning of wicker basket of manual scavengers (Daliya Jalao) became the hallmark of the drive. The policy of utilizing the services of people from scavenging community as masons in toilet construction made them their own change agent. Thus, the participatory approach made the initiative self reinforcing.
- The Balmiki organization in the district namely Rashtriya Balmiki Jan Vikas Manch, popularly known as Balmiki Sena was involved from the beginning of the drive. The approach and concern shown by the district administration resulted in Balmiki Sena's intensive mobilization for liberating manual scavengers. It also exerted social pressure on their fellow community members who were still engaged in the practice of manual scavenging.

- इस पहल के अन्य महत्वपूर्ण स्टेकधारक शुष्क शौचालयों के प्रयोक्ता थे। उन्हें शुष्क शौचालयों के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई और वे अपने शौचालयों को परिवर्तित करने के लिए आगे आए। पंचायत प्रतिनिधियों ने भी अपने गांवों से शुष्क शौचालयों का उन्मूलन करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लिया। पड़ोसी गांवों के लोग भी बहुत मददगार साबित हुए क्योंकि घरों के पास शुष्क शौचालयों के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती थीं।
- ग्राम स्तरीय सरकारी पदाधिकारीगण भी अपने घरों, अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों के घरों में शौचालयों का निर्माण कराने में सक्रिय भागीदार हो गए थे।

### परिणाम

- सभी 2750 सफाई कर्मियों को मुक्त करा लिया गया है। उनके बच्चों और परिवार के सदस्यों को सफलतापूर्वक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से संबद्ध कर दिया गया है तथा वे वैकल्पिक व्यवसायों जैसे कि राजमिस्त्री, भैंस पालन में लगे हैं। उनके बच्चों का स्कूल में नामांकन करा दिया गया है और उन्हें विशेष छात्रवृत्ति दी गई है।
- मौजूदा 50,000 शुष्क शौचालयों को समाप्त कर दिया गया है और जल-प्रवाह शौचालयों का उपयोग किया जा रहा है। इस अभियान के फलस्वरूप लोग 1500 रु० की सरकारी सहायता प्राप्त करके नए शौचालयों का निर्माण कर रहे हैं।
- सफाई कर्मियों के परिवार अब मैला ढोने की प्रथा का विरोध कर रहे हैं और उनकी महिलाएं बाल्मीकि सेना के साथ सक्रिय रूप से कार्य करके इस अमानवीय पेशे को छोड़ देने के लिए अन्य जिलों के सफाई कर्मियों को प्रेरित कर रही हैं। उन्होंने डलिया जलाओ को एक विरोधी कार्यनीति बना दिया है।
- गांवों में महामारी और बीमारियों में तेजी से गिरावट आई है। दस्त के मामले वर्ष 2009-10 के 18216 से घटकर वर्ष 2010-2011 में 12675 हो गए हैं। पल्स पोलियो राउंड में बीमार पाए गए बच्चों की संख्या 155 से घटकर 95 हो गई है। वर्ष 2009 में पोलियो के 52 मामले थे जो अब समाप्त हो गए हैं।
- चार सौ गांवों और ब्लाकों को कवर किया गया है। पांच हजार राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है जिनमें से 65 सफाई कर्मियों परिवारों से हैं।

## Category - Individual

---

---

- The other important stakeholders of the initiative were users of dry latrine. Informing them about the ill effects of dry latrine made them come forward to convert their toilets. Panchayat representatives also participated actively in eliminating dry latrine from their villages. People from neighboring villages were also very supportive as having dry latrine in nearby home caused health problems to them also.
- Village level government functionaries became active participants by constructing toilets in their homes and in their friend's and relative's homes.

### Outputs/Outcomes

- All the 2750 manual scavengers have been liberated. Their children and family members have been successfully linked to government welfare schemes and engaged in alternate trades like masonry, buffalo keeping. Their children have been enrolled in schools and have been given special scholarships.
- The existing 50,000 dry toilets have been removed and pour flush latrines are being used. As a result of the campaign, people are building new toilets by availing of government support of ₹ 1500.
- The families of manual scavengers are now opposing manual scavenging and their women are pro-actively working with Balmiki Sena to motivate manual scavengers in other districts to quit this inhuman occupation. They have made Daliya Jalao a counter hegemony strategy.
- There is a sharp decrease in epidemics and diseases in the villages. Diarrhea cases have come down from 18216 in 2009-2010 to 12675 in 2010-2011. The number of children found sick in pulse polio rounds has come down from 155 to 95. The number of polio cases which were 52 in 2009 are non-existent now.
- Four hundred villages and blocks have been covered. Five hundred masons have been trained, out of which 65 are from scavenger families.

**पहल - हुबली-धारवाड़ नगर के जलाशयों एवं उद्यानवनों का संरक्षण और नगर में सांस्कृतिक अभिवृद्धि**

पुरस्कार विजेता का नाम - श्री दर्पण जैन, भा.प्र.सेवा  
तत्कालीन उपायुक्त, धारवाड़

**परियोजना संक्षेप में**

भौगोलिक स्थिति, पश्चिम घाट और कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी हुबली-धारवाड़ के टिवन शहर को विशिष्ट बनाती है। जलाशयों के सूखने और पार्कों के अतिक्रमण, नालियों के पानी और कूड़े के कारण झीलों और पार्कों की स्थिति अत्यंत खराब थी। इसके अलावा, यह असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया था। मनोरंजन तथा खुले स्थान के अभाव ने श्री दर्पण जैन, उपायुक्त को शहर के खुले स्थानों और शहरी जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए प्रेरित किया ताकि स्थायी विकास प्राप्त किया जा सके और नागरिकों में विकास प्राधिकारियों के प्रति विश्वास की बहाली की जा सके।

पार्कों, खुले स्थान और मनोरंजन के स्थानों का पुनरुद्धार करने के अलावा इस परियोजना का अन्य उद्देश्य हुबली-धारवाड़, जो कभी हिन्दुस्तानी संगीत का गढ़ था, की सांस्कृतिक परम्परा को बहाल करना था।

**कार्यान्वयन विशेषताएं**

- एक पहल के तहत विभिन्न निकायों के नियंत्रणाधीन विभिन्न विभागों का अभिसरण (कंवर्जेंस)।
- शहर के पर्यावरणीय स्थायीत्व का पुनर्निर्माण करने के लिए व्यापक स्तरीय पहल की आवश्यकता के बारे में समझाना। इसके लिए अल्प महत्व वाले मदों के लिए निधियों का आबंटन करने की बजाय बृहत्तर उद्देश्य के लिए विभिन्न स्रोतों से निधियों का अभिसरण करना अपेक्षित था।
- वास्तुकारों को शामिल करते हुए भवनों की विशिष्ट स्थापत्यकला विशेषताओं को लागू करना।
- जिला निर्माण एजेंसी, धारवाड़ निर्मिती केंद्र जिसे कार्यान्वयन प्राधिकारी बनाया गया था, के सेवाओं का अधिकाधिक उपयोग करना जिससे निर्माण की लागत को कम करने में सहायता मिलती।
- संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक अवसंरचना के लिए पृथक न्यासों का सृजन करना और प्रयोक्ता शुल्क निर्धारित करना।
- प्रवेश टिकट, पार्किंग शुल्क, जलपान गृह और मनोरंजन क्षेत्र को लीज पर देने के माध्यम से प्राप्त राजस्व को परियोजना के रख-रखाव और स्थायीत्व पर खर्च किया गया।

## Category - Individual

---

---

### **Initiative - Saving Open Spaces and Urban Lakes (SOUL) and Cultural Rejuvenation of the Twin City of Hubli - Dharwad**

Name of the Awardee - Shri Darpan Jain, IAS  
then Deputy Commissioner, Dharwad

#### **Project in Brief**

The geographical location, at the cusp of the Western Ghats and beginning of the black cotton soil, make the twin cities of Hubli Dharwad unique. The state of lakes and parks in the twin cities deteriorated with the drying up of lakes and pollution of the parks due to encroachments, sewage and garbage disposal. In addition, they also became a hub for anti-social activities. Lack of recreational and open spaces encouraged Shri Darpan Jain, Deputy Commissioner to initiate revitalization of the city by restoring its open spaces and urban lakes to achieve sustainable development. This would also reinstate the trust of the citizens towards the development authorities.

In addition to the restoration of parks, open and recreational spaces, the second objective of the project was to restore the cultural legacy of Hubli-Dharwad, which was once the citadel for Hindustani music.

#### **Implementation Highlights**

- Convergence of different departments, which were under the control of different bodies, under one initiative.
- Inculcating the need for a macro level initiative towards rebuilding the environmental sustainability of the city. This required convergence of funds from various sources towards a larger objective rather than allocating them for smaller insignificant items.
- Introduction of unique architectural characteristic for the buildings by involving architects.
- Maximizing the use of services of the district construction agency, Dharwad Nirmithi Kendra which was made the implementing authority and helped in reduction of the cost of construction.
- Creation of separate trusts and user fees for each infrastructure set up to promote culture.
- Revenue through entry tickets, parking fees, lease of cafeteria and amusement area were directed towards the maintenance and sustainability of the project.

- विशिष्ट पहचान बनाते हुए पर्यावरण अनुकूल सांस्कृतिक रूप से सशक्त और उत्तम शहर का निर्माण करना।

### परिणाम

- यह पहल 40 करोड़ रु० मूल्य की अवसंरचना सृजित करने में सफल रही है।
- अवसंरचना के तहत सृजित विभिन्न सुविधाओं का प्रति माह एक लाख से अधिक लोग उपभोग कर रहे हैं। यह इस पहल की प्रभावकारिता का एक प्रमाण है।
- शहरी विकास के साथ हुबली-धारवाड़ के सांस्कृतिक विकास और पर्यावरण अनुकूल, सांस्कृतिक रूप से सशक्त और उत्तम शहर का निर्माण करने में सफल रहा है।
- प्रयोक्ता शुल्कों के जरिए राजस्व का सृजन इस पहल को पूरी तरह स्थायी बनाता है।

## Category - Individual

---

---

- Building of an environment friendly, culturally strong and healthy city while creating a unique identity.

### **Outputs/Outcomes**

- The initiative has been successful in creating infrastructure worth ₹ 40 crores.
- More than a lakh people are enjoying the various facilities created under the infrastructure every month. This is a testimony of the effectiveness of the initiative.
- The urban development along with the cultural development of Hubli-Dharwad has been successful in building an environment-friendly, culturally strong and healthy city.
- The generation of revenue through user fees makes the initiative fully sustainable.



**पहल - गन्ना सूचना प्रणाली**

- पुरस्कार विजेताओं के नाम -
1. श्री कामरान रिज़वी, भा.प्र.सेवा, तत्कालीन गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार
  2. श्री अमिताभ प्रकाश, तत्कालीन अपर गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार
  3. श्री राजेश कुमार पांडेय, तत्कालीन संयुक्त गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार
  4. श्री अनिल कुमार शर्मा तत्कालीन मुख्य अभियंता, उत्तर प्रदेश सरकार
  5. श्री सत्येंद्र सिंह, गन्ना उपायुक्त उत्तर प्रदेश सरकार
  6. डॉ० वीरेन्द्र बहादुर सिंह जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार

**परियोजना संक्षेप में**

किसी भी राज्य में गन्ना खरीद एक संवेदनशील मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में पूरे देश के गन्ना उत्पादन क्षेत्र का आधा भाग है। यह कानून और व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। अतः गन्ना खरीद का प्रबंधन एक कठिन और संवेदनशील मुद्दा है। इस खरीद की प्रक्रिया का प्रबंधन करने के लिए श्री कामरान रिज़वी के नेतृत्व में अधिकारियों के समूह ने कई उपाय किए जिसके फलस्वरूप बिना किसी सरकारी खर्च के गन्ना सूचना प्रणाली के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह परियोजना सरकार, निजी क्षेत्र और सहकारी समितियों के बीच सहयोगपूर्ण प्रक्रिया का परिणाम है। इस प्रणाली ने खरीद की एक पारदर्शी और आसान पद्धति को संभव बनाया तथा इससे किसान और उद्योग दोनों को लाभ हुआ।

**कार्यान्वयन विशेषताएं**

- **सहयोग:** इस प्रणाली की लागत को चीनी मिलों द्वारा वहन किया जाता है; उत्पादक समितियां अपना डाटाबेस उपलब्ध कराती हैं जबकि सरकार इस प्रणाली की आयोजनाकार, सहयोगी और समन्वयक थी।
- **पहुंच:** अलग-अलग साक्षरता स्तरों के सभी स्टैकहोल्डरों को पहुंच प्रदान करने के लिए 3 प्रणालियों, वेबसाइट (उच्च साक्षर जिनके पास पर्सनल कंप्यूटर हैं) एसएमएस और क्वेरी एसएमएस (मध्यम स्तर के साक्षर जो मोबाइल फोन प्रयोक्ता हैं), आईवीआरएस (अल्प साक्षर/निरक्षर जो लैंडलाइन/मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं) के जरिए सूचना उपलब्ध कराई जाती है। प्रभावी संप्रेषण के लिए एसएमएस की भाषा हिंदी में है।
- **हैंड हेल्ड कंप्यूटर:** पारम्परिक हस्तलिखित लेन-देन पर्ची के कारण होने वाली त्रुटियों को कम करने के लिए चीनी मिलों के खरीद केंद्रों पर हैंड हेल्ड कंप्यूटर संस्थापित किया गया था। हैंड हेल्ड कंप्यूटर चीनी मिल के मुख्य कंप्यूटर को प्रिंटर और जीपीआरएस से कनेक्ट करता है। हैंड हेल्ड कंप्यूटर वजन पर्ची का प्रिंट देता है और लेन-देन के बारे में एसएमएस भेजता है, यह सूचना उत्पादकों के डाटा बेस में स्वतः ही अद्यतन हो जाती है।

### Initiative - Sugarcane Information System, Uttar Pradesh

- Names of the Awardees -
1. Shri Kamran Rizvi, IAS, then Cane Commissioner, Govt. of Uttar Pradesh
  2. Shri Amitabh Prakash, Additional then Cane Commissioner, Govt. of UP
  3. Shri Rajesh Kumar Panday, then Joint Cane Commissioner, Govt. of UP
  4. Shri Anil Kumar Sharma then Chief Engineer, Govt. of UP
  5. Shri Sateyindra Singh, Deputy Cane Commissioner, Govt. of UP
  6. Dr. Virendra Bahadur Singh Distt. Cane Officer, Govt. of UP

### Project in Brief

Sugarcane procurement is a sensitive issue in any state. In Uttar Pradesh, which has half the national sugarcane producing area, it also has a bearing on law and order. Hence, management of sugarcane procurement is a difficult and sensitive issue. In order to manage this process of procurement, the team of officers led by Shri Kamran Rizvi, took measures that led to the development of sugarcane information system, at no cost to the Government. This project is an outcome of a collaborative process between the Government, private sector and the cooperative. The system has enabled a transparent and easy method of procurement and has benefitted both the farmer and the industry.

### Implementation Highlights

- **Collaboration:** The cost of the system was borne by the sugar mills; the Grower Societies provided their database, while the Government was the system planner, facilitator and integrator.
- **Accessibility:** To allow accessibility to all the stakeholders of varying literacy levels, the information is made available through 3 systems; a website (highly literate who have access to a PC), SMS & Query SMS (medium level literates who are mobile phone users) and through IVRS (low level literates/illiterates who use a landline/mobile phone). The language of the SMS was set in Hindi, for effective communication.
- **Hand Held Computer:** In order to reduce the errors due to traditional handwritten transaction slips, hand held computer was installed at the purchase centres of the sugar mills. The hand held computer connects the main computer of the sugar mill with a printer and a GPRS. The hand held computer prints a weight slip and sends an SMS regarding

- **मानकीकरण:** मानकों के केंद्रीकृत सेटिंग ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य के सभी चीनी मिल एक समान मानकों का पालन करे।
- दोष रहित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए 125 मिलों के प्रत्येक आईटी कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साथ ही तीन प्रणालियों के प्रभावी उपयोग के संबंध में किसानों को प्रशिक्षित किया गया।

### परिणाम

#### पूर्ण कवरेज

- मिल के कवरेज क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक किसान को कवर किया गया है।
- 125 चीनी मिलों को कवर किया गया है।
- एसआईएस के अंतर्गत गन्ना किसानों की संख्या 30,00,000 है।
- किसानों और चीनी मिलों के बीच बेहतर संवाद।
- इस परियोजना से 18,000 करोड़ रु० गन्ना क्रय और विक्रय में पूर्ण पारदर्शिता आई है।
- एसआईएस हर मिनट 30 लाख किसानों के 15.0 करोड़ पारस्परिक इंटरैक्शन/ ट्रांजेक्शन पर नजर रखता है।

#### वित्तीय लाभ

- कुल बचत - 1547.26 करोड़ रु०
  - किसान - 846.54 करोड़ रु०
  - चीनी मिल - 700.72 करोड़ रु०
- सरकार का कोई खर्च नहीं
- किसानों के लिए मुफ्त

#### प्रभावकारिता

- 145.77 मिलियन एसएमएस
- वेबसाइट पर 3.48 मिलियन हिट्स
- 2.76 मिलियन आईवीआरएस कॉल

#### सरकार को लाभ

- पारदर्शिता और बेहतर नियंत्रण
- अधिक दक्षता और प्रभावकारिता
- चीनी माफिया का खात्मा
- सरकार के प्रक्रिया स्तरों में कमी

#### चीनी मिलों को लाभ

- अधिक रस और शर्करा युक्त ताजा गन्ने की आपूर्ति
- उत्पादन में वृद्धि
- इष्टतम समय सारणी के कारण क्षमता का बेहतर उपयोग।

the transaction, the grower's database also gets automatically updated with this information.

- **Standardization:** Centralized setting of standards ensured that all the sugar mills in the state adhered to uniform standards.
- Training was provided to the IT personnel of each of the 125 mills to ensure flawless execution. The farmers were simultaneously trained on the effective use of the three systems.

### Outputs/Outcomes

#### Total Coverage

- Every farmer in the catchment areas of mills is covered.
- 125 Sugar Mills covered.
- Number of sugarcane farmers under SIS is 30,00,000.
- Improved communication between the farmers and the sugar mills.
- The project has brought in complete transparency in the sale and purchase of sugarcane worth ` 18,000 crore.
- SIS tracks 15.0 crore interactions/transactions of each of the 30 lakh farmers on a minute-minute basis.

#### Financial Benefit

- Total savings - ` 1547.26 crore
  - Farmers - ` 846.54 crore
  - Sugar Mills - ` 700.72 crore
- No cost to Government
- Free to farmers

#### Effectiveness

- 145.77 million SMS
- 3.48 million hits on website
- 2.76 million IVRS calls

#### Benefits to Government

- Transparency and better control
- Increased efficiency and effectiveness
- Elimination of sugar mafia
- Reduction in layers of Government

#### Benefits to Sugar Mills

- Supply of fresh sugarcane with higher juice and sucrose content
- Increase in production
- Better capacity utilization due to optimum scheduling.

**पहल - कर्नाटक में वाणिज्य कर प्रणाली का संपूर्ण रूपांतरण**

- पुरस्कार विजेताओं के नाम -
1. श्री प्रदीप सिंह खरोला, भा.प्र.सेवा  
वाणिज्य कर आयुक्त (सीसीटी)  
वाणिज्य कर विभाग  
कर्नाटक सरकार
  2. श्री अजय सेठ, भा.प्र.सेवा  
प्रधान सचिव (बीएंडआर)  
वित्त विभाग, कर्नाटक सरकार
  3. श्री सुबोध यादव, भा.प्र.सेवा  
वाणिज्य कर अपर आयुक्त  
वाणिज्य कर विभाग, कर्नाटक सरकार
  4. श्री एच. एन. जयपाल  
वाणिज्य कर अपर आयुक्त  
वाणिज्य कर विभाग, कर्नाटक सरकार
  5. श्री वेंकटेशन ए., उप महानिदेशक  
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
  6. श्री पी. वि. भट्ट, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक  
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
  7. श्री आर. ई. तिप्पेस्वामी  
वाणिज्य कर सहायक आयुक्त  
वाणिज्य कर विभाग, कर्नाटक सरकार

**परियोजना संक्षेप में**

वाणिज्य कर विभाग प्रति दिन होने वाले लाखों वाणिज्य कर लेन-देन का हिसाब सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। पारम्परिक रूप से ये प्रक्रिया हस्तचालित थी जिसका मानीटरिंग करना बहुत जटिल था। करदाताओं को प्रत्येक माह आयकर विवरणी, कर प्रेषण और अन्य औपचारिकताओं के लिए वास्तविक रूप से कार्यालय जाना पड़ता था। अत्यधिक मात्रा में कागजी दस्तावेज पर कार्रवाई करना और मूल्यांकन करना कठिन था। इसके अतिरिक्त, पारदर्शिता का अभाव था। इस प्रकार के परिदृश्य में विभाग के साथ इसके करदाताओं की पारस्परिक क्रिया को केवल 'इंटरनेट' के जरिए पारस्परिक क्रिया में परिवर्तित कर दिया गया। तदनुसार, आंतरिक प्रक्रियाओं, कानूनों और नियमों को वाणिज्य कर प्रणाली का रूपांतरण के पहल के अनुरूप परिवर्तित कर दिया गया। पूरे राज्य में मजबूत हार्डवेयर के अलावा नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए विभाग के भीतर और करदाताओं का क्षमता निर्माण करना अपेक्षित था।

### **Initiative - Transformation of Commercial Tax Regime in Karnataka**

- Names of the Awardees -
1. Shri Pradeep Singh Kharola, IAS, Commissioner of Commercial Taxes (CCT), Commercial Taxes Department Government of Karnataka
  2. Shri Ajay Seth, IAS, Principal Secretary (B&R), Finance Department Government of Karnataka
  3. Shri Subhodh Yadav, IAS, Addl. CCT, Commercial Taxes Department Government of Karnataka
  4. Shri H. N. Jaypal, Addl. CCT Commercial Taxes Department Government of Karnataka
  5. Shri Venkateshan A., Deputy Director General, National Informatics Centre
  6. Shri P. V. Bhat, Sr. Tech Director National Informatics Centre
  7. Shri R. E. Thippeswamy, Asst. CCT Commercial Taxes Department Government of Karnataka

### **Project in Brief**

The Commercial Taxes Department is responsible for ensuring that millions of commercial tax transactions that occur per day are being accounted for. Traditionally, these procedures were done manually, which complicated the task of monitoring. The tax payers were required to physically go to the offices every month to file returns, remit taxes and for other formalities. The bulky paper documentation was difficult to process and evaluate, besides lacking transparency. In the wake of such scenario, the interface of the Department with its taxpayers was converted to interaction through 'internet' only. The internal processes, laws and the rules were changed accordingly to suit the initiative of 'Transforming the Commercial Taxes'. In addition to the installation of robust hardware system across the state, capacity building within the department as well as the taxpayers was required to adopt the new technology.

### कार्यान्वयन विशेषताएं

- कर प्रशासन में एक नए प्रतिमान की शुरुआत करना जिसमें नई प्रणालियां और प्रक्रिया, स्वतः नीति निर्माण प्रणालियां शामिल हैं जो इस प्रकार हैं:
  - ई-एसयुजीएएम (सुगम)-(सिम्पल अपलोडिंग ऑफ गुड्स अराइवल एंड मूवमेंट)।
  - ई-एसयूवीईजीए (सुवेगा)-(सिम्पली अपलोड अबाऊट द व्हीकल एंड गो अक्रोस)।
  - ई-वीएआरएडीएएन (वरदान)-(वैट रजिस्ट्रेशन एंड डाक्यूमेंटेशन एक्सेस थ्रू इंटरनेट)।
  - ई-वीएआरएडीआई (वरादी)-(वैट रिटर्न एंड डाटा थ्रू इंटरनेट)।
- इसके अतिरिक्त, डीलरों द्वारा चेक भुगतान के समाशोधन की कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए ई-भुगतान के जरिए कर देयताओं के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण के साथ सांविधिक प्रपत्रों का ऑनलाइन जारी करने और शिकायत निवारण की शुरुआत की गई है। शिकायत निवारण और सेवाओं की प्रभावी और पारदर्शी प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए ई-ग्राहक (गारंटीड रेस्पॉस अगेंस्ट हिडन एक्टीविटीज ऑफ टैक्स एवेजन इन कर्नाटक) की शुरुआत की गई है।
- इस पहल ने विभाग को सेवा प्रदाता के रूप में पहचान दिलाई है। प्राप्त किए जाने वाले सभी भुगतान और प्रदान की जाने वाली सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप में की जाती हैं जिससे ई-गवर्नेंस का व्यापक उपयोग सरल हुआ है।
- विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, पारदर्शी कार्मिक नीति की शुरुआत की गई जिससे कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि हुई और उन्हें सभी प्रकार के कार्य करने का अवसर मिला।
- इसके अतिरिक्त, आंतरिक जवाबदेही को मजबूत बनाने के लिए ई-सीएएस (कम्प्रेहेन्सिव असेसमेंट सिस्टम) की शुरुआत की गई है।

### परिणाम

- इस पहल के कार्यान्वयन से दैनिक आधार पर विभाग में आने वाले लोगों की संख्या इस पहल के कार्यान्वयन से पहले के लगभग 30,000 लोगों से घटकर प्रतिदिन 1,000 लोगों से भी कम हो गई है।
- वर्ष 2011-12 में राजस्व में लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2010-2011 में यह 27 प्रतिशत था।
- प्रतिदिन कम से कम तीन टन कागज की बचत करके यह पहल पर्यावरण अनुकूल सिद्ध हुई है।
- औसत प्रतीक्षा समय सात मिनट से घटकर एक मिनट से भी कम हो गया है। सुवेग से पारगमन पास का समय एक घंटे से घटकर तीन मिनट हो गया है। इस पहल ने विभाग की पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि की है जिससे भ्रष्ट आचरणों का उन्मूलन हुआ है।
- इस पहल के कार्यान्वयन से कार्यालय-डीलर इंटरैक्शन समय, विभाग के वास्तविक दौरे के समय में काफी हद तक कमी आई है। इस प्रकार यह सेवा प्रदायगी के लिए प्रभावी और कुशल सिद्ध हुआ है।

### Implementation Highlights

- Introduction of a new paradigm in tax administration, which includes new systems and procedures, self policing systems like:
  - e-SUGAM (Simple Uploading of Goods Arrival and Movement).
  - e-SUVEGA (Simply Upload about the Vehicle and Go Across).
  - e-VARADAN (VAT registration and Documentation Access through Internet).
  - e-VARADI (VAT Return and Data through Internet).
- In addition, electronic remittance of tax dues through e-payment has been introduced for eliminating the hassle of clearing the cheque payment by the dealers, along with online issue of statutory forms and grievance redressal. e-GRAHAK (Guaranteed Response Against Hidden Activities of tax evasion in Karnataka) has been introduced for complaint redressal and to ensure effective and transparent delivery of services.
- The initiative recognizes the department as a service provider. All the payments to be received and the services delivered are done electronically.
- Training was conducted for the officers at various levels for capacity building. In addition, transparent personnel policies have been introduced which has increased the morale of the employees and gave them exposure to all types of jobs.
- In addition, e-CAS (Comprehensive Assessment System) has been introduced to strengthen internal accountability.

### Outputs/Outcomes

- Implementation of the initiative reduced the number of people coming to the department on a daily basis to less than 1,000 per day, from approximately 30,000 people before the implementation of the initiative.
- The revenue recorded a growth rate of about 22 per cent in 2011-2012. This was 27 per cent in 2010-2011.
- The initiative has proved to be environment friendly initiative with the saving of at least three tons of paper per day.
- The average waiting time has reduced from seven minutes to less than a minute. e-SUVEGA has reduced the time for transit pass from one hour to three minutes. The initiative has increased the transparency and accountability of the Department, thereby, eliminating corrupt practices.
- The office-dealer interaction time, time of physical visits to the department has been reduced to a large extent with the introduction of this initiative, thus, proving to be effective as well as efficient in service delivery.



**पहल - सिक्किम हिमालय की चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिवेश में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्कृष्टता**

संगठन का नाम - ग्रामीण प्रबंधन एवं विकास विभाग, सिक्किम सरकार

**परियोजना संक्षेप में**

सिक्किम एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई रेलमार्ग अथवा हवाई मार्ग संयोजकता नहीं है। संवेदनशील परिस्थितिकी तंत्र, कमजोर भूगर्भ के साथ भारी वर्षा के संयोग के फलस्वरूप बार-बार प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और सड़क मार्ग बंद होते रहते हैं। घर ढलान भू-भाग पर बने हुए हैं। यह परियोजना बुनियादी अवसंरचना और सेवाएं प्रदान करने, भूकंपरोधी मकान उपलब्ध कराने, पर्यटन संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देने, पहुंच बढ़ाने और कठिन प्राकृतिक परिस्थितियों में रहने वाले नागरिकों का विकास करने से संबंधित है। यह कार्य ग्रामीण विकास कार्य योजना (वीडीएपी) के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर दृष्टिकोण तथा बहु-क्षेत्र योजना तैयार करके विकेंद्रीकृत योजना पद्धति को अपनाते हुए किया जाता है।

**कार्यान्वयन विशेषताएं**

वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान परियोजना की विशेषताएं इस प्रकार थीं:

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा):** ग्राम पंचायतों को दिए गए कार्यक्रम का शत-प्रतिशत कार्यान्वयन। इसने संपूर्ण पर्वतीय भू-भाग में छोटे कार्यों को बढ़ावा दिया ताकि ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी और मांग को प्रोत्साहित किया जा सके। प्रचालनों की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण सामाजिक लेखा परीक्षा की गई।
- **मनरेगा-धारा विकास:** विशेषकर सूखा प्रभावित दक्षिण और पश्चिम जिलों में भूजल रिचार्ज करने, सूखते भूमिगत जल की समस्या का निवारण करने के लिए भू-जल विज्ञान तकनीक का उपयोग करके स्रोत का पुनरुद्धार करना। इस कार्यक्रम का विस्तार सूखते झीलों और जल-प्रवाह पर भी किया गया था। गूगल अर्थ पर 700 से अधिक जल स्रोत का वैज्ञानिक मानचित्रण करके ग्रामीण जल स्रोत एटलस तैयार किया गया।
- **स्वच्छता:** सिक्किम एकमात्र पहला राज्य है जिसने वर्ष 2008 में पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त किया है।
- **सिद्धेश्वर धाम:** वर्ष 2007 में संकल्पित एक नवीन तीर्थस्थल और पर्यटन पहल जो सोलोफोक सिक्किम में शुरू किया गया।
- **मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन:** संपूर्ण दृष्टिकोण के जरिए ग्रामीण गरीब की आवास स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सभी कच्चे मकानों को पक्के मकानों में बदलना। स्वामित्व मोड में एक मंजिला भूकंपरोधी 605 वर्गफुट प्लिंथ एरिया में कालम और टाई बीम के साथ मजबूत कंक्रीट ढांचे का प्रावधान।

## Category - Organization

---

---

### **Initiative - Excellence in Rural Management and Development in the Challenging Physical Environment of the Sikkim Himalaya**

Name of the Organization - Rural Management and Development Department  
Government of Sikkim

#### **Project in brief**

Sikkim is a region that has no rail or air connectivity. The combination of a fragile ecosystem, weak geology along with heavy rainfalls has resulted in frequent natural calamities and road blocks. The households are scattered over the steep terrain. The project deals with providing basic infrastructure and services, providing earthquake resistant housing, increasing tourism activities, increasing accessibility and development of the citizens who are living in difficult physical conditions. This is done by adopting a decentralized planning approach with the preparation of perspective and multi-sectoral plans at the gram panchayat level under the Village Development Action Plan (VDAP).

#### **Implementation highlights**

The following were the project highlights during the years 2008-09 to 2011-12:

- **Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA):** 100 percent implementation of the program given to gram panchayats. It promoted micro-works across the mountain terrain to encourage the participation of rural women and facilitate demand. Quality social audits were done to increase transparency of operations.
- **MGNREGA-Dhara Vikas:** Supplementing the ground water recharge, reviving springs using geo-hydrology techniques to address the problem of drying springs, especially in the drought prone South and West Districts. This program has also been extended to dried-up lakes and streams as well. The Village Spring Atlas was prepared by scientific mapping of more than 700 springs on Google Earth.
- **Sanitation:** Sikkim is the first and only state to accomplish 100 percent sanitation in 2008.
- **Sideshwar Dham:** An innovative pilgrimage and tourism initiative conceptualised in 2007, and undertaken in Solophok, Sikkim.
- **Chief Minister's Rural Housing Mission (CMRHM):** Conversion of all the kuccha houses to pukka houses for improving the qualitative housing status of the rural poor through saturation approach. Provision of single storied earthquake resistant, reinforced concrete frame structure with columns and tie beams with a 605 sqft plinth area with construction in owner driven mode.

- **लास्ट माइल जी2सी पब्लिक डिलीवरी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए ब्लॉक प्रशासन केंद्रों का सृजन:** विकेंद्रीकृत विकास पद्धति के भाग के रूप में ग्राम पंचायतों के समूह को प्रशासनिक लेखा और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए 29 ब्लॉक प्रशासनिक केंद्रों की स्थापना की गई है।
- **ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास कार्य योजना ( वीडिएपी ):** ग्राम विकास कार्य योजना (वीडीएपी) विकेंद्रीकृत योजना प्रक्रिया को औपचारिक रूप प्रदान करता है। बहु-क्षेत्र योजनाएं ग्राम पंचायत स्तरों पर तैयार की जाती हैं।
- **ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन संबंधी संवेदनशीलता आकलन:** यह आकलन जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतरसरकारी पैनल (आईपीसीसी) द्वारा निर्धारित प्रभाव, संवेदनशीलता और अनुकूलन क्षमता के मानक वैज्ञानिक प्रोटोकॉल का उपयोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर शुरू किया गया था।

### परिणाम

- गरीबी वर्ष 2004-05 के 30.9 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2009-10 में 13.1 प्रतिशत हो गई जो उल्लेखनीय रूप से वर्ष 2009-10 के राष्ट्रीय औसत 29.8 प्रतिशत से कम है।
- वर्ष 2011-12 में मनरेगा के जरिए कम से कम 65 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नियोजित किया गया; जबकि यह वर्ष 2007-08 में 22 प्रतिशत था।
- सिक्किम वर्ष 2008 में पूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने वाला एकमात्र पहला राज्य है।
- 2001 में 36.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2011 में कम से कम 87.2 प्रतिशत घरों में शौचालय हैं।
- छप्पर वाले मकानों की संख्या घटकर वर्ष 2011 में 6 प्रतिशत से कम हो गई है।
- जल की सुलभता (पेयजल के रूप में नल का पानी) वर्ष 2001 के 70.3 से बढ़कर वर्ष 2011 में 85.3 प्रतिशत हो गई है।

## Category - Organization

---

---

- **Creation of Block Administration Centres for strengthening last mile G2C public delivery system:** 29 Block Administrative Centres (BACs) have been established to provide administrative, accounts and technical support to a cluster of gram panchayats as part of the decentralized development approach.
- **Village Development Action Plan (VDAP) at Gram Panchayat Level:** The VDAP formalises the decentralized planning process. Multi-sectoral plans have been prepared at the gram panchayat level.
- **Climate Change Related Vulnerability Assessment at Gram Panchayat Level:** This assessment was undertaken at the gram panchayat level using standard scientific protocols of exposure, sensitivity, and adaptive capacity as prescribed by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

### Outputs and Outcomes

- Poverty has reduced from 30.9 percent (2004-05) to 13.1 percent (2009-10), which is significantly lower than the national average of 29.8 percent for the year 2009-10.
- At least 65 percent of the rural households were employed through the MGNREGA in the year 2011-12 whereas it was 22 percent in 2007-08.
- Sikkim is the first and only state to accomplish 100 percent sanitation in 2008.
- At least 87.2 percent of the households have access to toilets within their house (2011), as compared to 36.3 percent in the year 2001.
- The number of thatched roofed houses has been reduced to less than 6 percent in the year 2011.
- Accessibility to water (tap water as a source of drinking water) has increased from 70.3 percent in the year 2001 to 85.3 percent in the year 2011.

**पहल - कौशल्य वर्धन केंद्र**

संगठन का नाम - रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय, गुजरात सरकार

**परियोजना संक्षेप में**

गुजरात के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय, गुजरात सरकार ने स्वर्णिम गुजरात ग्राम्य कौशल्य वर्धन केंद्र (केवीके) योजना के अंतर्गत गांवों में गांव समूह प्रशिक्षण केंद्रों के जरिए युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। सामान्य क्षेत्र में 10,000 से अधिक की आबादी वाले शहरी गांवों तथा जनजातीय क्षेत्रों में 7,000 की आबादी वाले गांवों में लगभग 7 से 10 गांवों के समूह के लिए केवीके स्थापित करने का निर्णय लिया गया। उन गांवों पर भी बल दिया गया जहां राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं की शुरुआत नहीं की गई थी।

**कार्यान्वयन विशेषताएं**

- पाठ्यक्रम शुल्क किफायती हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रतिमाह 50/- रु० का नाममात्र का शुल्क लिया जाता है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/विकलांग अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। कौशल प्राप्त करने के लिए कोई उच्चतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं है।
- विभाग द्वारा जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी 1076 कौशलों की पहचान की गई है। इनमें से वर्तमान में 72 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में केवीके में प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिनमें रोजगार के बेहतर अवसर हैं।
- नई अवसंरचना के सृजन पर कोई व्यय नहीं हुआ था। सरकार और स्थानीय निकायों की मौजूदा अवसंरचनाओं का केवीके के लिए उपयोग किया गया। कुछ केवीके किराए के परिसरों पर संचालित किए गए।
- सभी 300 केवीके में डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) कनेक्शन हैं। अतः उपग्रह संचार (सैट-कॉम) के जरिए आवधिक विशिष्ट व्याख्यानों की व्यवस्था की जाती है।
- राज्य के सभी केवीके समन्वयकों की मासिक बैठक मुख्यालय में आयोजित की जाती है।
- योजना आयोग ने कौशल्य वर्धन केंद्र परियोजना की सराहना की है और वर्ष 2010-11 के लिए 125 करोड़ रु० की मंजूरी प्रदान की है।

## Category - Organization

---

---

### Initiative - Kaushalya Vardhan Kendra

Name of the Organization - Directorate of Employment and Training  
Government of Gujarat

### Project in Brief

With a goal of providing employment to the youth of Gujarat, the Directorate of Employment & Training, Government of Gujarat started imparting skill development training to youth through village cluster training centres in villages, under Swarnim Gujarat Gramya Kaushalya Vardhan Kendra (KVK) Yojana. It was decided to establish KVKs in urban villages having more than 10,000 population in general area and 7,000 population in tribal area for a cluster of around 7 to 10 villages. The emphasis was also on the villages where the vocational training facilities were not initiated by the State Government.

### Implementation Highlights

- The course fees are affordable. A nominal rate of ₹ 50 per month is charged for general candidates while schedule caste/ schedule tribe/ physically handicapped candidates and women are not charged any fees. There is no upper age limit for obtaining the skills. The trainees are not required to travel a long distance to avail the training.
- As many as 1076 skill sets useful for improving quality of life were identified by the department. Out of these, currently 72 training courses are being imparted in KVKs that have better employment opportunities.
- No expenditure was incurred on creation of new infrastructure. The existing infrastructures of government and local bodies were put to use for the KVKs. A few KVKs also operate on the rented premises.
- All the 300 KVKs have direct to home (DTH) connections. So, periodic special lectures are arranged through satellite communication (SAT-COM).
- Monthly meeting of all coordinators of KVK of the State are held at the head office.
- The Planning Commission has appreciated the Kaushalya Vardhan Kendra project and sanctioned ₹ 125 crores for the year 2010-11.

**परिणाम**

4.37 लाख से अधिक लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशिक्षुओं के रोजगार नियोजन में वृद्धि हुई है:

- o प्रशिक्षुओं की संख्या 3,64,091 से बढ़कर 6,26,413 हो गई है।
- o महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत 47 प्रतिशत (वर्ष 2010-11) से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 58.67 प्रतिशत (नवम्बर, 2012 तक) हो गया है।
- o केवीके ने ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं के बीच प्रशिक्षण संस्कृति के एक नए रूप को प्रोत्साहित किया है।
- o अनुसूचित जाति के प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2011-12 के 42240 से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 71615 हो गई है।
- o अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2011-12 के 91732 से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 154548 हो गई है।
- o अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2011-12 के 109756 से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 183086 हो गई है।
- o प्रशिक्षित विकलांग अभ्यर्थियों की संख्या वर्ष 2011-12 के 720 से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 1618 हो गई है।
- o निर्माण और बागवानी क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए अहमदाबाद नगर निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था।

## Category - Organization

---

---

### Outputs/Outcomes

More than 4.37 lakhs people have obtained training. This has increased the employability of the trainees from rural areas:

- o Increase in the number of trainees from 3,64,091 to 6,26,413.
- o Percentage of women participants increased from 47 percent (2010-11) to 58.67 percent (up to November-2012) in 2012-13.
- o KVKs have given impetus to a new form of training culture among the rural folks specially women.
- o Number of SCs trained increased from 42240 in 2011-12 to 71615 in 2012-13.
- o Number of STs trained also increased from 91732 in 2011-12 to 154548 in 2012-13.
- o Number of OBCs trained increased from 109756 in 2011-12 to 183086 in 2012-13.
- o Number of physically handicapped candidates trained increased from 720 in 2011-12 to 1618 in 2012-13.
- o MoU with Ahmedabad Municipal Corporation was entered into to train youth in the construction and gardening sectors.



**दिनांक 21 अप्रैल, 2012 को प्रदान किए गए  
वर्ष 2010-11 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए  
प्रधानमंत्री पुरस्कार**

1.	<b>पहल -</b>  पुरस्कार विजेता का नाम :	लीबिया में गृहयुद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए निःस्वार्थ सेवा करना  सुश्री मणिमेकलइ मुरुगेसन, भारतीय विदेश सेवा, लीबिया में तत्कालीन भारत की राजदूत
2.	<b>पहल -</b>  पुरस्कार विजेताओं के नाम :	<b>जम्मू एवं कश्मीर में पंचायत चुनाव का संचालन</b>  1. श्री माधव लाल, भा. प्र. से. मुख्य सचिव जम्मू एवं कश्मीर 2. श्री कुलदीप खोड़ा, भा. पु. से. पुलिस महानिदेशक, जम्मू एवं कश्मीर 3. श्री बी. आर. शर्मा, भा. प्र. से. मुख्य निर्वाचन अधिकारी जम्मू एवं कश्मीर 4. श्री आर. के. वर्मा, क. प्र. से. मुख्य सचिव के विशेष सचिव जम्मू एवं कश्मीर 5. श्री बी. बी. व्यास प्रधान सचिव (आयोजना एवं विकास)
3.	<b>पहल -</b>  पुरस्कार विजेताओं के नाम :	<b>संपूर्ण कन्वर्जेंस मोड में ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस त्रिपुरा</b>  1. सुश्री सौम्या गुप्ता जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर उत्तरी त्रिपुरा जिला

**Prime Minister's Awards for Excellence in  
Public Administration for the year 2010-11  
presented on 21<sup>st</sup> April, 2012**

1.	<b>Initiative-</b>  Name of the Awardee:	<b>Rendering selfless service to evacuate Indian Nationals amid civil war in Libya</b>  Ms. M. Manimekalai, IFS then Ambassador of India in Libya
2.	<b>Initiative-</b>  Names of the Awardees:	<b>Conduct of Panchayat Elections in Jammu and Kashmir</b>  1. Shri Madhav Lal, IAS Chief Secretary Jammu and Kashmir  2. Shri Kuldeep Khoda, IPS DGP, Jammu and Kashmir  3. Shri B. R. Sharma, IAS Chief Electoral Officer Jammu and Kashmir  4. Shri R. K. Varma, KAS Special Secretary to Chief Secretary Jammu and Kashmir  5. Shri B. B. Vyas Principal Secretary (Planning and Development)
3.	<b>Initiative-</b>  Names of the Awardees:	<b>Village Health and Nutrition Day in Complete Convergence Mode Tripura</b>  1. Ms. Saumya Gupta District Magistrate and Collector North Tripura District

		<p>2. डा. एस. एन. चौधरी जिला परिवार कल्याण और जिला निगरानी अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय त्रिपुरा सरकार</p> <p>3. श्री अमलेंदु भौमिक कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस) कुमारघाट, उत्तरी त्रिपुरा जिला त्रिपुरा</p> <p>4. श्री पिनाकी आचार्य तत्कालीन तकनीकी निदेशक एवं डी आई ओ सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तरी त्रिपुरा जिला केंद्र</p>
4.	<p><b>पहल -</b></p> <p>संगठन का नाम :</p>	<p><b>गुजरात राज्य में भागीदारी वैज्ञानिक जलागम प्रबंधन</b></p> <p>गुजरात राज्य जलागम प्रबंधन अभिकरण गुजरात</p>



		<p>2. Dr. S. N. Choudhuri, District Family Welfare &amp; District Surveillance Officer Ministry of Health and Family Welfare Government of Tripura</p> <p>3. Mr. Amalendu Bhowmik Programme Officer (ICDS) Kumarghat, North Tripura District Tripura</p> <p>4. Mr. Pinaki Acharya Technical Director and DIO Ministry of IT &amp; Communication National Informatics Centre North Tripura District Centre</p>
4.	<b>Initiative-</b>  Name of the : Organization	<b>Participatory Scientific Watershed Management in Gujarat State</b>  Gujarat State Watershed Management Agency, Gujarat

**दिनांक 21 अप्रैल, 2011 को प्रदान किए गए  
वर्ष 2009-10 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए  
प्रधानमंत्री पुरस्कार**

1.	<p><b>पहल -</b></p> <p>पुरस्कार विजेता का नाम :</p>	<p><b>दूरियों को पाटता - बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का कायापलट - एक सफल कहानी</b></p> <p>श्री प्रत्यय अमृत, भा. प्र. से., सचिव राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना</p>
2.	<p><b>पहल -</b></p> <p>पुरस्कार विजेताओं का नाम :</p>	<p><b>मल्कापुर 24x7 जल आपूर्ति स्कीम की सफलता की कहानी</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. श्री राजेंद्र गणेशलाल होलाणी मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, क्षेत्र औरंगाबाद</li> <li>2. श्री सदानंद काशीनाथ भोपाले सेक्शन अभियंता</li> <li>3. श्री सुनील यशवन्त बासुगडे सेक्शन अभियंता</li> <li>4. श्री उत्तम पांडुरंग बागडे सेक्शन अभियंता कार्यपालक अभियंता का कार्यालय महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्य प्रभाग, कराड़ जिला: सतारा</li> </ol>
3.	<p><b>पहल -</b></p> <p>पुरस्कार विजेताओं का नाम :</p>	<p><b>शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र ( ईटीसी ) - स्वप्न से यथार्थ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. श्री विजय शांतीलाल नाहटा भा. प्र. से., नगर आयुक्त नवी मुम्बई नगर निगम ( एनएमएमसी )</li> </ol>

**Prime Minister's Awards for Excellence in  
Public Administration for the year 2009-10  
presented on 21<sup>st</sup> April, 2011**

1.	<b>Initiative-</b>  Name of the Awardee:	<b>Bridging the Gap - The Turn around of Bihar Rajya Pul Nirman Nigam – A Success Story</b>  Shri Pratyaya Amrit, IAS, Secretary Rajya Pul Nirman Nigam Ltd., Patna
2.	<b>Initiative-</b>  Name of the Awardees:	<b>Success Story of Malkapur 24×7 Water Supply Scheme</b>  1. Mr. Rajendra Ganeshlal Holani Chief Engineer, Maharashtra Jeevan Pradhikaran, Region Aurangabad  2. Mr. Sadanad Kashinath Bhopale Section Engineer  3. Mr. Sunil Yashwant Basugade Section Engineer  4. Mr. Uttam Pandurang Bagade Section Engineer Office of the Executive Engineer Maharashtra Jeevan Pradhikaran Works Division, Karad District: Satara.
3.	<b>Initiative-</b>  Name of the Awardees:	<b>Education and Training Centre (ETC) - Dreams to Reality</b>  1. Mr. Vijay Shantilal Nahata, IAS Municipal Commissioner Navi Mumbai Municipal Corporation (NMMC)



		2. सुश्री वर्षा विश्वजीत भगत निदेशक - (ईटीसी)
4.	पहल -  संगठन का नाम :	सिकल सेल ऐनिमिया कंट्रोल प्रोग्राम गुजरात सरकार  स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवाएँ एवं चिकित्सा शिक्षा आयुक्तालय, गांधीनगर गुजरात
5.	पहल -  संगठन का नाम :	हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक कचरे का स्थायी प्रबंध: संकल्पना से नीति तक  पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीईएसटी) हिमाचल प्रदेश सरकार



		2. Ms. Varsha Vishwajeet Bhagat Director - ETC
4.	<b>Initiative-</b>  Name of the : Organization	<b>Sickle Cell Anemia Control Programme, Government of Gujarat</b>  Commissionerate of Health, Medical Services & Medical Education Gandhinagar, Gujarat
5.	<b>Initiative-</b>  Name of the : Organization	<b>Sustainable Plastic Waste Management in Himachal Pradesh: From Concept to Policy</b>  Department of Environment, Science and Technology (DEST) Government of Himachal Pradesh



**दिनांक 21 अप्रैल, 2010 को प्रदान किए गए  
वर्ष 2008-09 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए  
प्रधानमंत्री पुरस्कार**

1.	<p><b>पहल -</b></p> <p>पुरस्कार विजेता का नाम :</p>	<p><b>ढाँचों का अतिक्रमण हटाना - सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना जबलपुर, मध्य प्रदेश</b></p> <p>श्री संजय दुबे, भा. प्र. से. तत्कालीन समाहर्ता और जिलाधीश जबलपुर, मध्य प्रदेश</p>
2.	<p><b>पहल -</b></p> <p>पुरस्कार विजेता का नाम :</p>	<p><b>नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी, बालाघाट, मध्य प्रदेश</b></p> <p>श्री गुलशन बामरा, भा. प्र. से. तत्कालीन समाहर्ता और जिलाधीश बालाघाट, मध्य प्रदेश</p>
3.	<p><b>पहल -</b></p> <p>पुरस्कार विजेता का नाम :</p>	<p><b>औषधियों को किफायती बनाना चित्तौड़गढ़, राजस्थान</b></p> <p>डॉ. समित शर्मा, भा. प्र. से. तत्कालीन जिलाधीश चित्तौड़गढ़, राजस्थान</p>
4.	<p><b>पहल -</b></p> <p>पुरस्कार विजेता का नाम :</p>	<p><b>नदी संयोजन परियोजना, जलगांव, महाराष्ट्र</b></p> <p>श्री विजय सिंघल, भा. प्र. से. तत्कालीन समाहर्ता और जिलाधीश जलगांव, महाराष्ट्र</p>

**Prime Minister's Awards for Excellence in  
Public Administration for the year 2008-09  
presented on 21<sup>st</sup> April, 2010**

1.	<b>Initiative-</b>  Name of the Awardee:	<b>Removal of Encroachments of Structures - Maintaining Communal Harmony Jabalpur, Madhya Pradesh</b>  Shri Sanjay Dubey, IAS then Collector & District Magistrate Jabalpur, Madhya Pradesh
2.	<b>Initiative-</b>  Name of the Awardee:	<b>Involvement of Community in Naxalite-affected Areas Balaghat, Madhya Pradesh</b>  Shri Gulshan Bamra, IAS, then Collector and District Magistrate Balaghat, Madhya Pradesh
3.	<b>Initiative-</b>  Name of the Awardee:	<b>Making Medicines Affordable Chittorgarh, Rajasthan</b>  Dr. Samit Sharma, IAS, then District Magistrate, Chittorgarh Rajasthan
4.	<b>Initiative-</b>  Name of the Awardee:	<b>River Linking Project Jalgaon, Maharashtra</b>  Shri Vijay Singhal, IAS, then Collector & District Magistrate Jalgaon, Maharashtra

5.	<p><b>पहल -</b></p> <p>पुरस्कार विजेता का नाम :</p>	<p><b>गर्भाशय कैंसर की जांच- चेन्नई, तमिलनाडु</b></p> <p>श्री राजेश लखानी, भा. प्र. से., आयुक्त चेन्नई निगम, तमिलनाडु</p>
6.	<p><b>पहल -</b></p> <p>दल के सदस्यों के नाम :</p>	<p><b>धान की खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण छत्तीसगढ़</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. डॉ. आलोक शुक्ला, भा. प्र. से. तत्कालीन सचिव, एफसीएस एंड सीए विभाग</li> <li>2. श्री गौरव द्विवेदी, भा. प्र. से. तत्कालीन प्रबंध निदेशक 'मार्कफेड' और 'सीजीएससीएससी'</li> <li>3. श्री ए. के. सोमशेखर, वैज्ञानिक 'घ' राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र</li> </ol>
7.	<p><b>पहल -</b></p> <p>दल के सदस्यों के नाम :</p>	<p><b>वन अधिकारों को मान्यता मध्य प्रदेश</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. श्री ओ. पी. रावत, भा. प्र. से. प्रधान सचिव, मध्य प्रदेश सरकार</li> <li>2. श्री जयदीप गोविंद, भा. प्र. से. तत्कालीन आयुक्त जनजाति विकास</li> <li>3. श्री अनिल ओबरॉय भा. व. से. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक</li> </ol>

5.	<b>Initiative-</b>  Name of the Awardee:	<b>Cervical Cancer Screening Chennai, Tamil Nadu</b>  Shri Rajesh Lakhani, IAS Commissioner, Corporation of Chennai, Tamil Nadu
6.	<b>Initiative-</b>  Name of the Team Members:	<b>Computerization of Paddy Procurement and Public Distribution System, Chhattisgarh</b>  1. Dr. Alok Shukla, IAS then Secretary, Department of FCS & CA  2. Shri Gaurav Dwivedi, IAS then, Managing Director, ‘MARKFED’ & ‘CGSCSC’  3. Shri A. K. Somasekhar Scientist ‘D’, National Informatics Centre
7.	<b>Initiative-</b>  Name of the Team Members:	<b>Recognition of Forest Rights Madhya Pradesh</b>  1. Shri O. P. Rawat, IAS Principal Secretary Govt. of Madhya Pradesh  2. Shri Jaideep Govind, IAS then Commissioner Tribal Development  3. Shri Anil Oberoi, IFS Addl. Principal Chief Conservator of Forest

		<p>4. सुश्री रश्मि अरूण शामी, भा. प्र. से. तत्कालीन निदेशक, जनजाति क्षेत्र विकास आयोजना</p> <p>5. श्री अशोक कुमार उपाध्याय अपर निदेशक</p>
8.	<p>पहल -</p> <p>दल के सदस्यों के नाम :</p>	<p><b>समन्वित करदाता आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली ( आईटीडीएमएस )</b> <b>केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड</b> <b>भारत सरकार</b></p> <p>1. श्री एस. एस. खान, भा. रा. से. (आई.टी.), तत्कालीन आयकर महानिदेशक (जांच), नई दिल्ली</p> <p>2. श्री मिलाप जैन, भा. रा. से. (आई.टी.), आयकर महानिदेशक (जांच), नई दिल्ली</p> <p>3. श्री जी. टी. वेंकटेश्वर राव भा. रा. से. (आई.टी.), तत्कालीन आयकर अपर निदेशक (जांच) नई दिल्ली</p>
9.	<p>पहल -</p> <p>संगठन का नाम :</p>	<p><b>“प्रोजेक्ट एरो”- भारतीय डाक की कायापलट</b></p> <p>डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार</p>

		<p>4. Ms. Rashmi Arun Shami, IAS then Director, Tribal Area Development Planning</p> <p>5. Shri Ashok Kumar Upadhyay Additional Director</p>
8.	<p><b>Initiative-</b></p> <p>Name of the Team Members:</p>	<p><b>Integrated Taxpayer Data Management System (ITDMS) Central Board of Direct Taxes Government of India</b></p> <p>1. Shri S. S. Khan, IRS (IT), then Director General of Income Tax (Investigation), New Delhi</p> <p>2. Shri Milap Jain, IRS (IT) Director General of Income Tax (Investigation), New Delhi</p> <p>3. Shri G. T. Venkateswara Rao IRS (IT), then Additional Director of Income Tax (Investigation), New Delhi</p>
9.	<p><b>Initiative-</b></p> <p>Name of the Organisation:</p>	<p><b>‘Project Arrow’- Transforming India Post</b></p> <p>Department of Posts, Ministry of Communications &amp; IT Government of India</p>

**दिनांक 21 अप्रैल, 2009 को प्रदान किए गए  
वर्ष 2007-08 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए  
प्रधानमंत्री पुरस्कार**

1.	<p><b>पहल -</b></p> <p>पुरस्कार विजेता का नाम :</p>	<p><b>बंगलौर महानगर परिवहन निगम को वित्तीय सहायता कर्नाटक</b></p> <p>श्री उपेन्द्र त्रिपाठी, भा. प्र. से., तत्कालीन प्रबंध निदेशक, बंगलौर महानगर परिवहन निगम, कर्नाटक सरकार</p>
2.	<p><b>पहल -</b></p> <p>पुरस्कार विजेता का नाम :</p>	<p><b>प्राथमिक शिक्षा हेतु क्रिया आधारित विद्यार्जन ( एबीएल ) प्रणाली तमिलनाडु</b></p> <p>श्री एम. पी. विजय कुमार, भा. प्र. से. तत्कालीन आयुक्त, चैन्नई नगर निगम तमिलनाडु सरकार</p>
3.	<p><b>पहल -</b></p> <p>पुरस्कार विजेता का नाम :</p>	<p><b>युद्ध के दौरान बेरूत से भारतीय नागरिकों का निकास</b></p> <p>श्रीमती नेंगचा ल्होबुम, भा. वि. से. लेबनान में भारत की राजदूत</p>
4.	<p><b>पहल -</b></p> <p>पुरस्कार विजेता का नाम :</p>	<p><b>सुरक्षित मातृत्व एवं बाल संरक्षण कार्यक्रम</b></p> <p>डॉ. अमरजीत सिंह, भा. प्र. से. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, गुजरात सरकार</p>

**Prime Minister's Awards for Excellence in  
Public Administration for the year 2007-08  
presented on 21<sup>st</sup> April, 2009**

1.	<b>Initiative-</b>  Name of the Awardee:	<b>Financial Sustainability of Bangalore Metropolitan Transport Corporation, Karnataka.</b>  Shri Upendra Tripathy, IAS then Managing Director Bangalore metropolitan Transport Corporation, Government of Karnataka
2.	<b>Initiative-</b>  Name of the Awardee:	<b>Activity Based Learning (ABL) Methodology for Primary Education, Tamil Nadu</b>  Shri M. P. Vijaya Kumar, IAS then Commissioner of Chennai Municipal Corporation, Government of Tamil Nadu
3.	<b>Initiative-</b>  Name of the Awardee:	<b>Evacuation of Indian Nationals from Beirut during the war</b>  Mrs. Nengcha Lhouvum, IFS Ambassador of India in Lebanon
4.	<b>Initiative-</b>  Name of the Awardee:	<b>Safe Motherhood and Child Survival Programme</b>  Dr. Amarjit Singh, IAS Secretary, Health & Family Welfare Department, Government of Gujarat



5.	<p><b>पहल -</b> दल के सदस्यों के नाम :</p>	<p><b>स्कोर : बिहार में ई-पंजीकरण</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. श्री अनिल कुमार, भा. प्र. से. आईजी, पंजीकरण</li> <li>2. श्री दिलीप कुमार, एआईजी पंजीकरण</li> <li>3. श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह</li> <li>4. श्री बरूणा नंदन सिंह</li> <li>5. श्री निर्मल किशोर प्रसाद, एसएसए</li> <li>6. श्री संजय कुमार, एसएसए बिहार सरकार</li> </ol>
6.	<p><b>पहल -</b> दल के सदस्यों के नाम :</p>	<p><b>एमसीए 21-एक नई-गवर्नेंस परियोजना</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. श्री अनुराग गोयल, भा. प्र. से. सचिव, एमसीए</li> <li>2. श्री युद्धवीर सिंह मलिक, भा. प्र. से., तत्कालीन संयुक्त सचिव एमसीए</li> <li>3. डॉ. (सुश्री) शीला भिडे, भा. प्र. से., तत्कालीन संयुक्त सचिव एमसीए</li> <li>4. श्री आर. चंद्रशेखर, भा. प्र. से. तत्कालीन अपर सचिव (आई.टी.)</li> <li>5. श्री जितेश खोसला, भा. प्र. से. संयुक्त सचिव, एमसीए</li> <li>6. श्री एस. श्रीधरन, कनिष्ठ विश्लेषक, एमसीए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार</li> </ol>

5.	<p><b>Initiative-</b></p> <p>Name of the Team Members:</p>	<p><b>SCORE: e-Registration in Bihar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Shri Anil Kumar, IAS IG Registration</li> <li>2. Shri Dilip Kumar, AIG Registration</li> <li>3. Shri Birendra Kumar Singh</li> <li>4. Shri Baruna Nandan Singh</li> <li>5. Shri Nirmal Kishor Prasad SSA</li> <li>6. Shri Sanjay Kumar, SSA Government of Bihar</li> </ol>
6.	<p><b>Initiative-</b></p> <p>Name of the Team Members:</p>	<p><b>MCA21 – an e-Governance Project</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Shri Anurag Goel, IAS Secretary, MCA</li> <li>2. Shri Yudhvir Singh Malik, IAS then JS, MCA</li> <li>3. Dr. (Ms.) Sheela Bhide, IAS then JS, MCA</li> <li>4. Shri R. Chandrashekhar, IAS then AS (IT)</li> <li>5. Shri Jitesh Khosla, IAS, JS MCA</li> <li>6. Shri S. Sridharan, JA, MCA Ministry of Corporate Affairs Government of India</li> </ol>

7.	<p><b>पहल -</b></p> <p>दल के सदस्यों के नाम :</p>	<p><b>बेहतर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभ्यास</b> <b>जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. डॉ. रोहित यादव, भा. प्र. से. जिला अधिकारी</li> <li>2. सुश्री रितु सेन, भा. प्र. से. जिला अधिकारी (डी एवं आर) जिला: सरगुजा, छत्तीसगढ़ सरकार</li> </ol>
8.	<p><b>पहल -</b></p> <p>दल के सदस्यों के नाम :</p>	<p><b>मणिपुर में कार्मिक सूचना प्रणाली का</b> <b>कम्प्यूटरीकरण</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. श्री जरनैल सिंह, भा. प्र. से. तत्कालीन प्रधान सचिव</li> <li>2. श्री आर. आर. रश्मि, भा. प्र. से.</li> <li>3. श्री एस. सुंदरलाल सिंह, भा. प्र. से.</li> <li>4. श्री के. राधाकुमार सिंह, भा. प्र. से.</li> <li>5. श्रीमती एम. बुद्धिमाला देवी</li> <li>6. श्रीमती ओ. शालिजा चनु मणिपुर सरकार</li> </ol>
9.	<p><b>पहल -</b></p> <p>संगठन का नाम :</p>	<p><b>जोखिम प्रबंध प्रणाली ( आरएमएस )</b> <b>का कार्यान्वयन</b></p> <p>प्रणाली तथा आँकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय केंद्रीय उत्पाद तथा सीमाशुल्क बोर्ड भारत सरकार</p>

7.	<b>Initiative-</b>  Name of the Team Members:	<b>Improved Health and Sanitation Practices, District Surguja Chhattisgarh</b>  1. Dr. Rohit Yadav, IAS District Collector 2. Ms. Ritu Sain, IAS, DC (D&R) District : Surguja Government of Chhattisgarh
8.	<b>Initiative-</b>  Name of the Team Members:	<b>Computerization of Personnel Information System in Manipur</b>  1. Shri Jarnail Singh, IAS then Chief Secretary 2. Shri R. R. Rashmi, IAS 3. Shri S. Sunderlal Singh, IAS 4. Shri K. Radhakumar Singh, IAS 5. Smt. M. Budhimala Devi 6. Smt. O. Shaliza Chanu Government of Manipur
9.	<b>Initiative-</b>  Name of the Organisation:	<b>Implementation of the Risk Management System(RMS)</b>  Directorate General of Systems & Data Management Central Board of Excise and Customs Government of India

**दिनांक 21 अप्रैल, 2008 को प्रदान किए गए  
वर्ष 2006-07 हेतु लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए  
प्रधानमंत्री पुरस्कार**

1.	<b>पहल -</b> पुरस्कार विजेता का नाम :	<b>त्रिची सामुदायिक पुलिस व्यवस्था</b> श्री जे. के. त्रिपाठी, भा. पु. से. पुलिस महानिरीक्षक आर्थिक अपराध स्कन्ध तमिलनाडु सरकार
2.	<b>पहल -</b> पुरस्कार विजेता का नाम :	<b>मातृत्व एवं बाल संरक्षण तथा स्वास्थ्य में सुधार करना ( तमिलनाडु )</b> सुश्री शीला रानी चुकंट, भा. प्र. से. अध्यक्ष तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड
3.	<b>पहल -</b> पुरस्कार विजेता का नाम :	<b>ठाणे एवं नागपुर ( महाराष्ट्र ) शहरों का बदला स्वरूप</b> डॉ. टी. चन्द्रशेखर, भा. प्र. से. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र आवास तथा क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मुंबई
4.	<b>पहल -</b> दल के सदस्यों का नाम :	<b>लोकवाणी - नागरिकों को अधिकारिता देने का एक प्रयास ( उत्तर प्रदेश )</b> (i) श्री आमोद कुमार, भा. प्र. से. (ii) सुश्री जोहरा चटर्जी, भा. प्र. से. (iii) श्री एस. बी. सिंह

**Prime Minister's Awards for Excellence in  
Public Administration for the year 2006-07  
presented on 21<sup>st</sup> April, 2008**

1.	<b>Initiative-</b>  Name of the Awardee:	<b>Trichy Community Policing</b>  Shri J. K. Tripathy, IPS Inspector General of Police Economic Offences Wing Government of Tamil Nadu
2.	<b>Initiative-</b>  Name of the Awardee:	<b>Improving Maternal and Child Survival and Health (Tamil Nadu)</b>  Ms. Sheela Rani Chunkath, IAS Chairperson Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Ltd.
3.	<b>Initiative-</b>  Name of the Awardee:	<b>Changing Face of Thane &amp; Nagpur Cities (Maharashtra)</b>  Dr. T. Chandra Shekar, IAS Vice President & CEO Maharashtra Housing & Area Development Authority Mumbai
4.	<b>Initiative-</b>  Name of the Team Members :	<b>Lokvani-an effort to empower the Citizen (Uttar Pradesh)</b>  (i) Shri Amod Kumar, IAS (ii) Ms. Zohra Chaterjee, IAS (iii) Shri S B Singh

		<p>(iv) श्री उमा शंकर सिंह  (v) श्री देवेन्द्र पाण्डे  (vi) श्री ए.पी. सिंह</p>
5.	<p><b>पहल -</b>  दल के सदस्यों का नाम :</p>	<p><b>सूचना प्रौद्योगिकी लेखा परीक्षा पहल</b></p> <p>(i) श्री गौतम गुहा, भा.ले. तथा ले.प. सेवा  (ii) श्री एल.एस. सिंह, भा.ले. तथा ले.प. सेवा  (iii) श्री राजेश गोयल, भा.ले. तथा ले.प. सेवा  (iv) श्री नीलेश कुमार शाह, भा.ले. तथा ले.प. सेवा  (v) डॉ. आशुतोष शर्मा, भा.ले. तथा ले.प. सेवा</p>
6.	<p><b>पहल -</b>  दल के सदस्यों का नाम :</p>	<p><b>संरक्षित क्षेत्रों का कारगर प्रबंधन-उत्तराखंड</b></p> <p>(i) सुश्री ज्योत्सना स्टिलिंग, भा.वन.से.  (ii) श्री ए. के. बनर्जी, भा.वन.से.</p>
7.	<p><b>पहल -</b>  दल के सदस्यों का नाम :</p>	<p><b>अनारक्षित टिकट प्रणाली-रेल मंत्रालय</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. श्री विक्रम चोपड़ा आई आर टी एस</li> <li>2. डॉ. राजेश नारंग</li> <li>3. श्री टी वेंकटसुब्रमणियन् आईआरएसएमई</li> <li>4. श्री आर चन्द्रशेखर</li> <li>5. श्री रमन बंसल</li> <li>6. सुश्री मोनिका मल्होत्रा</li> <li>7. श्री आलोक चतुर्वेदी आई आर टी एस</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>(iv) Shri Uma Shankar Singh</li> <li>(v) Shri Devendra Pande</li> <li>(vi) Shri A P Singh</li> </ul>
5.	<p><b>Initiative-</b></p> <p>Name of the Team Members:</p>	<p><b>Information Technology Audit Initiative</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Shri Gautam Guha IA&amp;AS</li> <li>(ii) Shri L S Singh, IA&amp;AS</li> <li>(iii) Shri Rajesh Goel, IA&amp;AS</li> <li>(iv) Shri Neelesh Kumar Sah IA&amp;AS</li> <li>(v) Dr. Ashutosh Sharma IA&amp;AS</li> </ul>
6.	<p><b>Initiative-</b></p> <p>Name of the Team Members:</p>	<p><b>Effective Management of Protected Areas – Uttarakhand</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Ms. Jyotsna Sitling, IFS</li> <li>(ii) Shri A. K. Banerjee, IFS</li> </ul>
7.	<p><b>Initiative-</b></p> <p>Name of the Team Members:</p>	<p><b>Unreserved Ticketing System – Ministry of Railways</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Shri Vikram Chopra, IRTS</li> <li>2. Dr. Rajesh Narang</li> <li>3. Shri T. Venkatasubramanian IRSME</li> <li>4. Shri R. Chandrashekar</li> <li>5. Shri Raman Bansal</li> <li>6. Ms. Monica Malhotra</li> <li>7. Shri Alok Chaturvedi IRTS</li> </ol>



		8. श्री टी किरण कुमार 9. श्री कौस्तव मंडल 10. श्री देबाशीष घोष 11. श्री जी.जे. जैरी औरिक सिंह 12. श्री कपिल भगत 13. श्री प्रोजिनेश विस्वास 14. श्री दिलीप मिश्रा 15. श्री संदीप कुमार वत्स 16. श्री आशीष अरोड़ा 17. श्री गौरव डी. जौहरी 18. श्री नितिन गोयल 19. श्री पंकज कुमार 20. श्री आशीष विश्वकर्मा 21. श्री गौरव जैन 22. श्री बालू लाल धाकड़ 23. श्री रीतेश लाल 24. श्री प्रेम कुमार 25. श्री महेन्द्र जे. दुबे 26. श्री मोहम्मद शाहिद 27. श्री अंजनी कुमार मलिक 28. श्री दर्शन
8.	पहल -  दल के सदस्यों के नाम :	राजर्षि शाहू सर्वांगीण कार्यक्रम जिला परिषद् कोल्हापुर, महाराष्ट्र  (i) श्री देशमुख प्रभाकर कृष्ण जी भा.प्र.से. (ii) श्री माने महावीर दामोदर

		8. Shri T. Kiran Kumar 9. Shri Kaustav Mandal 10. Shri Debashish Ghosh 11. Shri G. J. Jerrie Auric Singh 12. Shri Kapil Bhagat 13. Shri Projinesh Biswas 14. Shri Dileep Mishra 15. Shri Sandeep Kumar Vats 16. Shri Ashish Arora 17. Shri Gaurav D. Johari 18. Shri Nitin Goyal 19. Shri Pankaj Kumar 20. Shri Ashish Vishwakarma 21. Shri Gaurav Jain 22. Shri Balu Lal Dhaker 23. Shri Ritesh Lal 24. Shri Prem Kumar 25. Shri Mahender J Dubey 26. Shri Mohd. Shahid 27. Shri Anjani Kumar Malik 28. Shri Darshan
8.	<b>Initiative-</b>  Name of the Team Members:	<b>Rajarshi Shahu Sarvangin        Karyakram, Zilla Parishad        Kolhapur, Maharashtra</b>  (i) Shri Deshmukh Prabhakar- Krishnaji, IAS (ii) Shri Mane Mahavir Damodar

9.	<p><b>पहल -</b></p> <p>दल के सदस्यों के नाम :</p>	<p>दिल्ली सरकार विद्यालय पद्धति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में मूलभूत सुधार</p> <p>(i) श्री राजेन्द्र कुमार, भा.प्र.से. (ii) श्री विजय कुमार, भा.प्र.से. (iii) श्रीमती गीतांजली जी कुन्द्रा भा.प्र.से. (iv) श्री अशोक कुमार</p>
10.	<p><b>पहल -</b></p> <p>दल के सदस्यों के नाम :</p>	<p>जम्मू और कश्मीर राज्य में भूकम्प की आपातक स्थिति में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन</p> <p>(i) श्री बी. बी. व्यास, भा.प्र.से. (ii) श्री बशरत अहमद धर, भा.प्र.से. (iii) श्री बशीर अहमद रुनियाल भा.प्र.से. (iv) श्री अब्दुल मजीद खाण्डेय क.प्र.से. (v) श्री जयपाल सिंह, क.प्र.से. (vi) श्री सईद शरीफ-उद्-दीन, क.प्र.से. (vii) श्री मोहम्मद रमजान ठाकुर क.प्र.से.</p>
11.	<p><b>पहल -</b></p>	<p>जल और स्वच्छता प्रबंध संगठन ( डब्ल्यू ए एस एम ओ ) - “गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में नवीनतम भागीदारी पेय जल प्रदायगी पहुंच” -गुजरात सरकार</p>

9.	<b>Initiative-</b>  Name of the Team Members:	<b>Radical Improvement in Delhi Government School System Government of NCT of Delhi</b>  (i) Sh. Rajendra Kumar, IAS (ii) Sh. Vijay Kumar, IAS (iii) Smt. Gitanjali G Kundra, IAS (iv) Sh. Ashok Kumar
10.	<b>Initiative-</b>  Name of the Team Members:	<b>Extraordinary Performance in Emergent Situation of Earthquake in the State of J&amp;K</b>  (i) Shri B. B. Vyas, IAS (ii) Shri Basharat Ahmad Dhar, IAS (iii) Shri Bashir Ahmad Runiyal, IAS (iv) Shri Abdul Majid Khanday KAS (v) Shri Jai Pal Singh, KAS (vi) Shri Syed Sharief-ud-din KAS (vii) Shri Mohammad Ramzan Thakur, KAS
11.	<b>Initiative-</b>	<b>Water &amp; Sanitation Management Organisation (WASMO) – “Innovative Participatory Drinking Water Delivery Approach in Rural Areas of Gujarat” – Government of Gujarat</b>

12.	पहल -	राज्य गरीबी उन्मूलन अभियान कुडुम्बश्री - “आश्रय - निराश्रय की पहचान, पुनर्वास और मॉनीटरिंग परियोजना” - केरल सरकार
13.	पहल -	इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवायें ( ई-सेवा ) - आंध्र प्रदेश सरकार
14.	पहल -	उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण, ( ओपीईपीए ) - “उड़ीसा में बाल खोज प्रणाली” - उड़ीसा सरकार



12.	<b>Initiative-</b>	<b>State Proverty Eradication Mission, Kudumbashree – ‘Asraya – Destitute Identification, Rehabilitation and Monitoring Project’ - Government of Kerala</b>
13.	<b>Initiative-</b>	<b>Electronically Deliverable Services (e-Seva) – Government of Andhra Pradesh</b>
14.	<b>Initiative-</b>	<b>Orissa Primary Education Programme Authority (OPEPA) – “Child Tracking System in Orissa”- Government of Orissa</b>

दिनांक 21 अप्रैल, 2007 को प्रदान किये गये  
वर्ष 2005-06 हेतु लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए  
प्रधानमंत्री पुरस्कार

---

---

1. श्री राजीव चावला, भा.प्र.से. - “भूमि-कर्नाटक में भूमि अभिलेखों की ऑनलाइन प्रदायगी” पहल हेतु।
2. श्री आर. एस. पाण्डेय, भा.प्र.से. - “नागालैंड में सार्वजनिक संस्थानों और सेवाओं के सामुदायिकीकरण का कार्यक्रम” पहल हेतु।

**Prime Minister's Awards for Excellence in  
Public Administration for the year 2005-06  
presented on 21<sup>st</sup> April, 2007**

---

---

1. Shri Rajeev Chawla, IAS – for the initiative “Bhoomi – Online delivery of land records in Karnataka”.
2. Shri R.S. Pandey, IAS – for the initiative “Programme of Communitization of Public Institutions and Services in Nagaland”.